

बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

03 मार्च 2023

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी]. कुल प्रश्न 27

अनुदान की राशि कबतक

*71 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना)ः

- (क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1846, दिनांक 21.01.2008 के द्वारा संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में वित्त रहित शिक्षा की समाप्ति की गई और उसी दरम्यान छात्र-छात्राओं के उत्तीर्णता के आधार पर संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को सत्र 2005-08 से 2008-11 तक का अनुदान निर्गत किया गया;
- (ख) क्या यह सही है कि सत्र 2009-12 से 2014-17 तक का इन अनुदानित महाविद्यालय का संबंधन राज्य सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण उनका अनुदान रोक दिया गया, जबिक इन महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधन की सारी प्रक्रिया कराकर राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु संबंधित संचिका विश्वविद्यालय से भेजी गई थी, जिनमें अधिकतर महाविद्यालयों का वर्तमान में स्थायी संबंधन प्राप्त हो चूका है;
- (ग) क्या यह सही है कि मा० उच्च न्यायालय के वाद सं० सी.डब्लू.जे.सी. 15062/2019, दिनांक 25.07.2019 में पारित आदेश में शिवपूजन शास्त्री, समता महाविद्यालय, दिनारा, रोहतास को संबंधन देते हुए राज्य सरकार से मिलने वाले सारे लाभ को देने हेतु आदेश निर्गत हुआ लेकिन उसका अनुपालन अबतक विभाग द्वारा नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान में संबद्धता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों को सत्र 2009-12 से 2014-17 तक के अनुदान की राशि का अविलम्ब भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार

*72 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार स्कूली शिक्षा की बेहतरी के साथ-साथ उसे गुणात्मक बनाने हेतु 'सेवा पूर्व प्रशिक्षण' तथा 'सेवाकालीन प्रशिक्षण' के माध्यम से बेहतरीन शिक्षकों को तैयार करने के लिए एक शिक्षण-प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

कन्या उत्थान योजना का लाभ

*73 मो. फारूक (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि शिवहर डिग्री कॉलेज की छात्राओं को अभी तक कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय की छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई पर विचार

*74 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार)ः

- (क) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के बजट में शिक्षा प्राथमिकता में है, लेकिन राज्य के लिए स्वीकृत केंद्रांश में केंद्र सरकार द्वारा लगातार कटौती और राशि मिलने में विलंब से राज्य सरकार को बहुत अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ रहा है;
- (ख) क्या यह सही है कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्रांश 9 हजार 425 करोड़ 76 लाख रुपए के स्थान पर मात्र 1860 करोड़ रुपए मिले हैं

और यदि राज्य सरकार अपनी तरफ से इंतजाम नहीं करती तो शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता;

- (ग) क्या यह सही है कि राज्य में 3 लाख 52 हजार नियोजित शक्षकों के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा एक लाख 90 हजार शिक्षकों के वेतन के लिए राशि स्वीकृत की गई है जिसके परिणामस्वरूप एक लाख 62 हजार शिक्षकों को पूरा वेतन भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से देने को विवश है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार ने केंद्र की उपेक्षापूर्ण नीति के विरुद्ध अबतक कौन से कदम उठाये हैं और सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में निर्धारित शर्तों की केंद्र द्वारा उपेक्षा पर क्या-क्या वैधानिक एवं कानूनी कार्रवाई की जा रही है?

गांधी संग्रहालय का निर्माण कबतक

*75 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक)ः

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में चम्पारण जाने के क्रम में पांच दिनों के लिए स्व. गया प्रसाद सिंह के रमना, मुजफ्फरपुर स्थित निजी आवास में प्रवास किए थे;
- (ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने उक्त जमीन पर गांधी संग्रहालय बनाने की घोषणा चार वर्ष पूर्व की थी और उसी क्रम में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार को 7 मार्च, 2019 में संबंधित जमीन की रिजस्ट्री कर दी गई है, इसके बावजूद अबतक उक्त स्थान पर गांधी संग्रहालय का निर्माण नहीं कराया जा सका है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर पर गांधी संग्रहालय का निर्माण कबतक कराना चाहती है?

शौचालय निर्माण एवं सफाई पर विचार

*76 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक)ः

- (क) क्या यह सही है कि 'यू डायस रिपोर्ट' के अनुसार पूरे राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक 90 फीसदी विद्यालयों में शौचालय है, लेकिन 50 फीसदी स्कूलों के शौचालय में मूलभूत चीजें (पानी, नल, दरवाजा, सफाई) उपलब्ध नहीं होने से इस्तेमाल नहीं होता है;
- (ख) क्या यह सही है कि राज्य के कई विद्यालय राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय

पुरस्कार के लिए नामित हुए थे लेकिन शौचालय की सफाई नहीं होने से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से बाहर हो गए;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालयों में विद्यार्थी की संख्या के अनुपात में शौचालय निर्माण तथा निर्मित शौचालय की प्रतिदिन सफाई किए जाने हेतु नीति बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अर्धनिर्मित भवन का निर्माण

*77 श्री सच्च्दानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय, तरैया में प्रखंड संसाधन केन्द्र का भवन वर्ष 2005 से बन रहा है जो 17 वर्ष बाद भी अर्धनिर्मित है;
- (ख) क्या यह सही है कि भवन अर्धनिर्मित होने के कारण शिक्षकों को बैठक करने तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में परेशानी हो रही है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अर्धनिर्मित भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बकाये वेतन का भुगतान

*78 श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा)ः

- (क) क्या यह सही है कि श्रीमती नीलिमा कुमारी, स॰शि॰ कन्या मध्य विद्यालय, गर्दनीबाग, पटना, दिनांक 29.01.2022 से दिनांक 03.03.2022 तक रूग्णावकाश में थी, जिसकी स्वीकृति जिला कार्यक्रम पदा॰ (स्थापना) पटना के पत्रांक 2612, दिनांक 23.03.2022 के द्वारा दी गयी है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षिका 31.12.2022 को सेवानिवृत्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक माह फरवरी, 2022 का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है;
- (ग) क्या यह सही है कि चिह्नित बालक मध्य विद्यालय, पुनाईचक, पटना द्वारा तीन बार टी.डी.एस बना कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के कार्यालय को समर्पित किया जा चुका है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सेवानिवृत्त शिक्षिका का वेतन भुगतान कबतक करना चाहती है?

नैक की मान्यता

*79 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के अंतर्गत पांच अंगीभूत एवं 19 सम्बद्ध कॉलेज हैं;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त अंगीभूत एवं सम्बद्ध कॉलेजों में एक को भी नैक से मान्यता प्राप्त नहीं है;
- (ग) क्या यह सही है कि नैक से मान्यता प्राप्त नहीं होने के चलते इन कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा अंतर्गत अंगीभूत एवं सम्बद्ध कॉलेजों को नैक से मान्यता प्राप्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रयोगशाला का संचालन

*80 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि स्कूल एवं कॉलेज में प्रयोगशाला की अहम भूमिका होती है, जिससे छात्र सैद्धांतिक रूप से सीखी हुई बातों को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, इससे छात्र की जिज्ञासा सन्तुष्ट होती है, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, तर्क -शक्ति और निरीक्षण शक्ति आदि बढ़ती है;
- (ख) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकतर स्कूल एवं कॉलेज की प्रयोगशाला में उपकरण/केमिकल की घोर कमी है, कई स्कूल एवं कॉलेजों में टेक्नीशियन के पद लगभग खाली पड़े हैं, कई वर्षों से इनकी नियुक्ति नहीं हुई है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिन स्कूल एवं कॉलेजों में प्रयोगशाला संचालित नहीं हो रही है वहां शीघ्र प्रयोगशाला संचालित कराने का विचार रखती है?

भवनों के निर्माण पर विचार

*81 श्री संजय पासवान (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के नरहट प्रखंड अन्तर्गत ग्राम मिल्की तथा ग्राम नारायणपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो गया है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्यालयों में भवन निर्माण

*82 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के नवसृजित प्रखण्ड नवीनगर पंचायत हिरहर उड़दाना में प्रा० वि०, शिकरिया रतन का अपना भवन नहीं रहने के कारण छात्र/ छात्राओं को काफी असुविधा होती है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में ज्यादातर दलित और महादलित के बच्चे पढ़ते हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि उक्त प्रखण्ड में लगभग 13 विद्यालय हैं और सबका अपना भवन नहीं है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खण्ड 'क' में वर्णित विद्यालय के साथ प्रखण्ड के सभी विद्यालयों में भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

नियमावली में संशोधन

*83 श्री खालिद अनवर (विधान सभा)ः

- (क) क्या यह सही है कि बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड की नियमावली वर्ष 2022 में बनाई गई थी;
- (ख) क्या यह सही है कि इस नियमावली के बनाने में मदरसा चलाने वालों से राय नहीं ली गई थी;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मदरसा चलाने वालों से भी राय लेकर उक्त नियमावली में संशोधन करना चाहती है, यदि हां तो

सामान्य वेतनमान देने पर विचार

*84 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC No 7651/2017 के आदेश में Physical Instructor and Physical Teacher बहाल करने का निर्देश दिया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग (द्वारा वित्त विभाग) के पत्रांक 793, दिनांक 14.05.2020 में महालेखाकार (लेखा हकदारी) के पत्र संख्या 9 पर अंकित किया गया है कि मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक अथवा शारीरिक अनुदेशक के पद हैं;
- (ग) क्या यह सही है कि विभागीय पत्रांक 366, दिनांक 30.03.22 के द्वारा राज्य के मध्य विद्यालय में 8386 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की समय सारणी जारी की गई जो विभागीय पत्रांक 1378, दिनांक 17.12.2021 के अनुरूप अंशकालीन की और नियमावली, 2020 होगी, पुनः विभागीय पत्रांक 504, दिनांक 04.05.2022 के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि बहाली नियमावली, 2012 के अनुरूप होगी;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमावली, 2012 और उससे पहले के नियम से बहाल कर्मी को वेतनमान दिया गया है तो Physical Instructor and Physical Teacher को भी सामान्य वेतनमान देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

निर्देश देने का विचार

*85 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा)ः

- (क) क्या यह सही है कि माध्यमिक और प्राइमरी विद्यालयों की शिक्षिकाओं का मातृत्व अवकाश छः माह कर दिया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है जिससे घरेलू खर्चा एवं बच्चों के लालन पालन में कठिनाई होती है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मातृत्व

अवकाश के दौरान वेतन का भुगतान नियमित रूप से करने का संबंधित पदाधिकारियों को निदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

भवन का निर्माण

*86 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि गया जिले के इमामगंज प्रखण्ड की बिराज पंचायत के बिराज गांव में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बिराज के भवन निर्माण का कार्य वर्ष 2015 में प्रारंभ हुआ था, परन्तु आज तक इसका निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि भवन निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण छात्रों एवं शिक्षकों को काफी परेशानी होती है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्कूल का निर्माण

*87 डा. रामवचन राय (मनोनीत)ः

- (क) क्या यह सही है कि पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में भूतनाथ रोड स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यालय के पीछे एक प्लॉट सरकारी विद्यालय खोलने हेतु वर्षों से चिह्नित है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी में कहीं कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं को निजी विद्यालयों में पढने के लिए विवश होना पडता है;
- (ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा आजतक उक्त प्लॉट में विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया है जिससे उक्त जमीन का अतिक्रमण हो रहा है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त चिह्नित प्लॉट पर शीघ्र स्कूल का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

इंक्रीमेंट पर विचार

*88 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल वेतन में सरकार 01 अप्रैल, 2021 से 15 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जबिक न तो उनकी प्रोन्नित हुई है, न ही वेतन का उन्नयन ही हुआ है;
- (ख) क्या यह सही है कि शिक्षकों को जनवरी एवं जुलाई, में जो भी पहले हो, वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन विभागीय आदेश के पत्रांक 1816 के अनुसार 15 प्रतिशत अप्रैल में मूल वेतन में वृद्धि के बाद जुलाई में वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं देकर 18 माह बाद जनवरी, 2020 में वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जायेगा, जुलाई में वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं होने से शिक्षकों को 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट का नुकसान हो रहा है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन शिक्षकों का, 15 प्रतिशत मूल वेतन में वृद्धि के बाद, जुलाई में ही वार्षिक इंक्रीमेंट देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई पर विचार

*89 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के प्रखण्डान्तर्गत ग्राम पंचायत राज बसुआरी में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय, रौदी टोल, बसुआरा में कभी कोई शिक्षक के नहीं आने के कारण विद्यालय का संचालन विगत कई वर्षों से पूर्णतः ठप और बंद हो गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, घोघरडीहा के संज्ञान में इसकी जानकारी रहने के बावजूद उक्त विद्यालय की ऐसी दयनीय स्थिति बनी हुई है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस दिशा में सरकार के द्वारा अबतक क्या कार्रवाई की गई?

प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में

*90 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि दिनेश चौधरी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, वैशाली संप्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में लाभुक योजना की राशि 66,98,300 गैर अनुदानित विद्यालय में लिखित लेकर उपलब्ध करवा दी;
- (ख) क्या यह सही है कि विभागीय स्वीकृत आदेश में अनुदानित विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को लाभ आधारित योजना की राशि दिए जाने का प्रावधान है;
- (ग) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली ने अपने पत्रांक 155, दिनांक — 15.09.2022 के द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना के प्रतिनिधित्व किया है;
- (घ) क्या यह सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अपने पत्रांक 155, दिनांक 26.10.2022 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी से स्पष्टीकरण पूछते हुए दिनांक 10.11.22 तक जवाब देने को कहा था, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी अबतक कार्रवाई नहीं की गयी है;
- (ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनियमितता करने के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी, श्री दिनेश चौधरी को निलंबन करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण

*91 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा)ः

- (क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज बसुआरी में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बगराहा में वर्ग — 8 तक की पढ़ाई होती है, जहां 8 शिक्षक पदस्थापित हैं और 455 छात्र/छात्राएं नामांकित हैं जबकि इसके विपरीत मात्र 2 कमरे का जर्जर भवन है जो किसी भी समय ध्वस्त होकर गिर सकता है;
- (ख) क्या यह सही है कि विद्यालय में आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है और बरसात के दिनों में विद्यालय पानी से चारों तरफ घिर जाने के कारण करीब-करीब 6 महीनों तक बन्द रहता है;
- (ग) क्या यह सही है कि विद्यालय के पास मात्र 1 कट्ठा जमीन है, जिस पर सभी वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए उपयुक्त कमरों का निर्माण कराना संभव नहीं है;

यदि उपर्युकृत खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय से 100 गज की दूरी पर खाता संख्या – 361 पुराना, नया – 1200, खेसरा – 1853 पुराना, नया – 5028, रकवा – 4 कट्ठा १८ धूर एवं खाता – ३६२ पुराना, नया – १२००, खेसरा – 1852 पुराना, नया — 5029, रकवा — 5 कट्ठा १९ धूर से संबंधित सरकारी गैरमजरूआ आम जमीन पर उपयुक्त कमरों के विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो कयों?

बेंच-डेस्क आपूर्ति कराने के संबंध में

श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार)ः *92

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा प्रखंड के पकठौल पंचायत में उतक्रमित मधय विद्यालय, किरतौल अवसथित है;
- क्या यह सही है कि उकत विद्यालय के 6 कमरों में 900 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं; (ख)
- क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के सिर्फ कक्षा 8 में विद्यार्थियों के बैठने हेतु (ग) बेंच-डेसक उपलब्ध है;
- क्या यह सही है कि विद्यालय में बेंच-डेस्क तथा मूलभूत सुविधाएं देने के लिए विद्यालय प्रबंधन ने कई बार विभाग से पत्राचार किया है:
- यदि उपर्युकृत खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा प्रखंड के पकठौल पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, किरतौल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच-डेस्क की आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन निर्माण कबतक

श्री भीसम साहनी (विधान सभा)ः *93

- क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड बगहा 1 में वर्ष 1929 में देवीमंगल राजकीय उचचतर विद्यालय की सथापना की गई थी;
- क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में सैकड़ों छात्र-छात्राएं पठन-पाठन करते (ख) हैं:

- (ग) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित दो मंजिला भवन टीन शेड में रहने के कारण जर्जर स्थिति में हो गया है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित विद्यालय भवन का निर्माण नये सिरे से कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

लाईब्रेरियन बहाली कबतक

*94 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत)ः

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है राज्य में 2008 में पहली बार लाईब्रेरियन की बहाली 2789 पदों को सृजित किया गया था जिसमें 1841 पदों पर नियुक्ति हुई शेष 928 पदों पर रिक्त रह गये;
- (ख) क्या यह सही है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9360 बिहार सरकार की नियमावली के अनुसार विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष एवं कनीय पुस्तकालय अध्यक्ष का होना आवश्यक है;
- (ग) क्या यह सही है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाईब्रेरियन की स्वीकृति मिल जाती है तो बिहार में कुल 16,879 पदों पर लाईब्रेरियन की नियुक्ति होगी;
- (घ) क्या यह सही है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सातवें चरण की शिक्षक की नियुक्ति के साथ ही लाईब्रेरियन की नियुक्ति की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है जबिक वाणिज्य शिक्षकों के लिए अलग से एस.टी.ई.टी. का आयोजन किया गया है;
- (ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाईब्रेरियन के पद पर कबतक नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मूर्ति की स्थापना

*95 श्री अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार)ः

क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि मधेपुरा स्थित बी०पी० मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्व० बी०पी० मंडल जी की प्रतिमा की स्थापना का निर्णय लिया गया था;
- (ख) क्या यह सही है कि प्रतिमा की स्थापना के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों

द्वारा सरकार से अनुरोध भी किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बी०पी० मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज मधेपुरा में स्व० बी०पी० मंडल की मूर्ति की स्थापना कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नामकरण करने पर विचार

*96 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि एस.एच. बिहारी एक महान कलाकार थे;
- (ख) क्या यह सही है कि एस.एच. बिहारी, आरा की माटी के लाल थे;
- (ग) क्या यह सही है कि राज्य सरकार बिहार में उनके नाम से किसी संस्था का नाम रखकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नामकरण करना चाहती है?

कड़ी कार्रवाई पर विचार

*97 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा)ः

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में भोजपुरी भाषा में अश्लील/द्विअर्थी तथा भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाले गानों की बाढ़ आ गई है;
- (ख) क्या यह सही है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थलों/समारोहों/चौक-चौराहों पर सार्वजनिक यातायात के साधनों पर अक्सर भोजपुरी भाषा में अश्लील/द्विअर्थी तथा भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाला गाना बजते रहता है;
- (ग) क्या यह सही है कि इन अश्लील/द्विअर्थी तथा भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाले गानों के बजने से बच्चों, महिलाओं तथा परिवार के साथ जा रहे व्यक्ति को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है;
- (घ) क्या यह सही है कि कम उम्र के बच्चे, युवा पर इन अश्लील/द्विअर्थी तथा

भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाले गानों का कुप्रभाव पड़ रहा है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है एवं लैंगिक हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुरी भाषा में बजने वाले इन अश्लील/द्विअर्थी गाना तथा भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाले गाना गाने वाले कलाकारों पर प्रतिबंध लगाते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?
